



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बीसवीं किस्त जारी करेंगे।
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कार निकोबार में जिला स्तरीय 'संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया।
- दक्षिण अंडमान जिले में बिना वैध लाइसेंस के होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट को संचालित करने की अनुमति नहीं है।
- कार निकोबार के विभिन्न गांवों में मीली बग और रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ्लाई पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बीसवीं किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आयोजित करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को तीन किस्तों में छह हजार रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं और प्रत्येक किस्त हर चार महीने में जारी की जाती है।



नीति आयोग के निर्देशानुसार, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कार निकोबार में जिला स्तरीय 'संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निकोबार जिला उपायुक्त अमित काले ने विभिन्न विभागों के ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 'संकल्प से सिद्धि' पहल के तहत सफल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और टीबी से उबरे लोगों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। समारोह में अंतर-विभागीय सहयोग का प्रदर्शन देखने को मिला। विभिन्न विभागों द्वारा जिले में चल रही कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों को प्रदर्शित करने के लिए सूचनात्मक कियोस्क भी स्थापित किए गए थे।



दक्षिण अंडमान जिले में राष्ट्र विरोधी ताकतों के संदिग्ध गैर गतिविधियों को रोकने और जनता तथा उनकी सम्पत्तियों की रक्षा के लिए जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की ओर से सभी होटल, आतिथि आवासों, लॉज और होम स्टे मालिकों के लिए लिखित आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें ही जिले में संचालित करने की अनुमति है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में समुचित मात्रा में सीसी टीवी कैमरा भी होने चाहिए, जिसके जरिए लोगों के परिसरों में प्रवेश और निकासी का पता चल सके। सभी कैमरा कार्य

करने की स्थिति में हो और कवरेज को कम से कम तीस दिनों तक संरक्षित रखना होगा। ऐसे सभी संस्थानों को परिसर में रहने वाले लोगों के बारे में पूर्ण जानकारी रखने के लिए रजिस्टर भी बनाए रखना होगा और संबंधित लोगों की वैध पहचान की कॉपी भी रिकॉर्ड के लिए रखनी होगी। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को फार्म सी भरकर निर्धारित अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा। यह आदेश लागू हो चुका है, जो अगले साठ दिनों तक जारी रहेगा। आदेश में इसका पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा दो सौ आठ के तहत कार्रवाई की जाएगी।



दक्षिण अंडमान ज़िले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप-किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि इस निर्णय से असामाजिक तत्वों के भागने या छिपने पर रोक लगाया जा सकता है और इससे लोगों की सुरक्षा तथा ज़िले में शांति को भी कायम किया जा सकेगा। आदेश के तहत किसी भी मकान मालिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक या मालिकों को किराएदारों या पेइंग गेस्ट को रखने से पहले स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। नौकर के संबंध में भी यह आदेश लागू होगा। आदेश अगले साठ दिनों तक लागू रहेगी।



छियहत्तरवें वन महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से डॉलीगंज स्थित डेयरी प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन फार्म, पशुधन फार्म परिसर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। 'एक पेड़ माँ के नाम' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और द्वीपों में हरियाली को बढ़ाना था। कार्यक्रम में विभाग की सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा प्रदान किए गए कुल सौ फलदार पौधे और अन्य पौधे लगाए गए।



चाथम स्थित एन वी वी एन संयंत्र के बंद होने के कारण पांच मेगावाट बिजली की कमी के कारण श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के आसपास के क्षेत्रों में बिजली से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान बिजली संकट से निपटने के लिए विभाग ने आम जनता, उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और होटल व्यवसायियों से शाम के समय बिजली का किफायती इस्तेमाल करने की अपील की है।



कृषि विभाग की ओर से कार निकोबार के विभिन्न गांवों में नारियल, फलों और सब्जियों में मीली बग और रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ़्लाई पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संक्रमण के लक्षणों की पहचान करने और मीली बग और रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ़्लाई के विरुद्ध प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिला प्रशासन, जनजातीय परिषद, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्र ने इस समस्या के समाधान के लिए

अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनाई हैं। किसानों को फसलों में कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए उचित अंतराल पर नियमित निरीक्षण, छंटाई और स्वच्छता बनाए रखने जैसी कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जानकारी दी गई।



ब्रिचगंज के बफल रेंज में एक सौ आठ माउंटेन ब्रिगेड मुख्यालय की ओर से कल छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास सुबह साढ़े नौ बजे से दिन में एक बजे तक चलेगा। सभी संबंधितों से स्वयं को और अपने वाहन तथा मवेशियों को अभ्यास के दौरान फायरिंग रेंज से दूर रखने को कहा गया है।



अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने अपने सभी कर्मचारियों को पुलिस वेतन पैकेज का लाभ प्रदान करने के लिए पच्चीस जनवरी, दो हजार तेईस को भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यापक पैकेज में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में चालीस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल है। सड़क दुर्घटना में दिवंगत जुएल तिग्गा की मृत्यु के बाद दुर्घटना बीमा के दावे को इस पैकेज के तहत सहायता प्रदान किया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने बीमा दावों के वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। जिससे पुलिस वेतन पैकेज के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित हुई है।



समाचार पत्रों की सुर्खियां

अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी सहित चार स्थलों के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मांगने के समाचार को **द डेली टेलीग्राम्स** और **द्वीप समाचार** ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अंडमान में पांच लकजरी इको टूरिज़्म रिसॉर्ट बनेंगे—जिनमें से एक निर्जन एविस द्वीप पर भी होगा—इस खबर को भी अखबार ने प्रमुखता से छापा है। **द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी** ने सांसद बिष्णु पद रे के वित्त मंत्री से मुलाकात कर द्वीपसमूह के लिए पांच वर्षों के लिए बजट आवंटन के साथ—साथ पांच हजार करोड़ रुपये के विशेष अनुदान के आग्रह के समाचार को प्रथम पृष्ठ में जगह दी है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष देखभाल वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित करने के समाचार को **इंफो इंडिया** ने जबकि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली के किफायती इस्तेमाल करने की अपील के समाचार को **द इको ऑफ इंडिया** ने प्रकाशित किया है।

